

नवाचार को सूचित कर सकती हैं। इससे अधिक टिकाऊ और चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन को गति देने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

चक्रीय अर्थव्यवस्था की धारणा ने हाल के दिनों में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है क्योंकि यह वर्तमान रैखिक आर्थिक मॉडल के लिए स्थाई समाधान प्रदान करती है। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को थासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है। अपशिष्ट को कम किया जाता है और उत्पादों को उनके जीवन के अंत में पुनः उपयोग या पुर्ननवीनीकरण के लिए डिजाइन किया जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से भारत को पर्यावरण संरक्षण से लेकर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन तक कई लाभ मिलने की उम्मीद है। ऊर्जा दक्षता और संसाधन अनुकूल पर चक्रीय अर्थव्यवस्था का ध्यान आयातित संसाधनों और परिवहन से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर भारत की निर्भरता को कम करने में भी योगदान दे सकता है। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था भारत में संसाधन सुरक्षा और लचीलेपन में सुधार कर सकती है। भारत तेल कोयला और खनिज जैसे आयातित संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। उत्पादन के स्थानीयकरण और स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करने पर चक्रीय अर्थव्यवस्था का जोर भारत की संसाधन सुरक्षा और लचीलेपन में सुधार कर सकता है। जिससे वैश्विक मूल्य में उतार चढ़ाव और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के प्रति इसकी संवेदनशीलता चलता कम हो सकती है।

संदर्भ सूची:-

- Global sustainable Development Report -2019.
- Albert Hanemaier and Maikel Krishna (April-2023) "Integral circular economy Report-2023.
- Policies to Enhance sustainable Development- OECD (2021).
- Department of economic affairs (Jan-2024) "The Indian Economy A Review".
- Jakshon Iin (EC) sustainable Development commission (Page n.-67-75 & 93-101).
- अय्यर आनंदी (निर्देशक फ़ाउंडेटर ऑफिस इंडिया) फ़ाउंडेटर इनोवेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म "सर्कुलर इकोनॉमी तथा संतत् समाधान (पृष्ठ स0-3-41)।
- सिंह पूजा (जून 2021) "भारत में संतत् आर्थिक विकास की चुनौतियाँ" (IJRAR) पृष्ठ स0 71-79।
- सरमा प्रसाद शंकर, भल्ला गोयल शालिनी, कुमार मौसम (अप्रैल 2023) "चक्राकार अर्थव्यवस्था के साथ भारत की कोशिश।"
- सर्कुलर रिपोर्ट-2023।
- फाउंडेशन ई0एम0 (2016) "भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था: दीर्घकालिक समृद्धि के लिए विकास पर पुर्नविचार।"
- गीसडोएरफर, मार्टिन, पाउलो सैवा गेट, नैन्सी एम0पी0 बोकेन व एरिक जॉन-2017 (जनरल ऑफ क्लीनर प्रोडक्सन्स) "सर्कुलर इकोनॉमी-एक नया स्थिरता प्रतिमान?" पृष्ठ सं0 757-768।



चक्रीय तथा सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जरूरी उपाय:-

1-वैधानिक उपाय :- उत्पादन चक्र के प्रारंभिक चरणों में पुनर्चक्रण/द्वितीय कच्चे माल की खरीद के लिए विधायी आदेशों और नियामक दृष्टिकोण से चक्रीय अर्थव्यवस्था को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत कानून के विकास के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है।

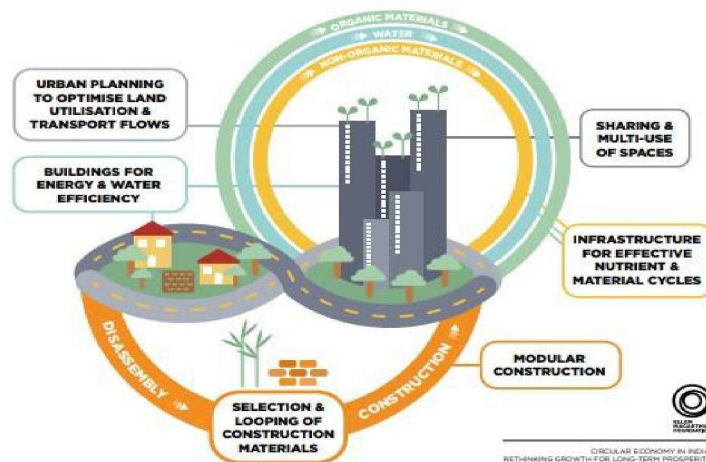
2-चक्रीय अर्थव्यवस्था रिपोर्टिंग पर एक सुव्यवस्थित ढांचे एपीआर प्रमाण पत्रों के कारोबार के संबंध में तंत्र को स्पष्टता प्रदान करने और आपूर्ति श्रृंखला की पूर्णता के लिए व्यवसाय को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने से भी इस दिशा में सहायता मिलेगी।

3-चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभों को प्राप्त करने के लिए सरकार की विभिन्न पहलों को उद्योग जगत के सहयोग के साथ क्रियान्वयन योग्य कार्रवाई के संयोजन में होना चाहिए।

4-अनुसंधान एवं विकास में निवेश नवकरणीय ऊर्जा उद्योग को पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए। अनुसंधान और विकास में निवेश पुनर्चक्रण के नए तरीके खोजने में मदद कर सकता है जिससे उच्च दक्षता और पर्यावरणीय रूप से कम छतिकारी फुटप्रिंट जैसे परिणाम प्राप्त होंगे उद्योगों को घरेलू अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना के लिए वैश्विक पुनर्चक्रण फर्मों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में भी अग्रसर होना चाहिए।

5-प्रौद्योगिकी प्रेरित पुनर्चक्रण- सरकार को अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संवर्धन में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और स्कूल स्तरों पर अपशिष्ट पुनर्चक्रण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके साथ ही शहरों में जैविक अपशिष्टों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपोजिट केंद्र स्थापित किये जा सकते हैं। जिससे मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता समाप्त होगी।

6-देश के निर्माण उद्योग में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को लागू करने की तुरंत आवश्यकता है। निर्माण अपशिष्ट पार्टिकुलर मैटर (पीओएम) के परिणाम स्वरूप कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है जो वायुमंडल में जारी होते हैं और निर्माण उद्योगों को एक पर चक्रीय अर्थव्यवस्था ढांचे के तहत लाने से इन मुद्दों को कम करने में मदद मिलेगी।



7. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों चक्रीय बिजनेस मॉडल जैसे उत्पाद ए सेवा और शेयरिंग प्लेटफार्म के लिए नए अवसर बनाने में मदद कर सकती हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रिसर्च में निवेश करने के नए ज्ञान और अंतर दृष्टि उत्पन्न करने में मदद मिल सकती है जो नीति व्यावसायिक रणनीतियों और



2—स्वच्छ भारत मिशन:— जब अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण के पहलुओं की बात आती है तो यह एक और महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप है । स्वच्छ भारत मिशन 2014 में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था । इस मिशन में अपशिष्ट पृथक्करण पुनर्चक्रण और खाद बनाने को बढ़ावा देने की पहल शामिल है और इसका उद्देश्य भारत को शून्य अपशिष्ट देश बनाना है ।

3—अटल इन्नोवेशन मिशन:— चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने तर्क के संदर्भ में सबसे अलग है वह है अटल इन्नोवेशन मिशन भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में अटल इन्नोवेशन मिशन शुरू किया गया था मिशन के समर्थन की पहल तथा विकास और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को अपने को प्रोत्साहित करना है ।

4—वित्तीय प्रोत्साहन:— उपर्युक्त प्रयासों के अलावा भारत सरकार ने चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को अपने और टिकाऊ भोग पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन लागू किए हैं । इन प्रोत्साहनों में रीसाइकलिंग उद्योग के लिए कर लाभ सब्सिडी और कम ब्याज वाले ऋण शामिल हैं ।

चुनौतियां:— चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत के नीतिगत ढांचे में चक्रीय बिजनेस मॉडल को अपनाने, संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने और अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए कई उपाय शामिल हैं । यह नीतियों और पहल भारत के संतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश के भीतर अधिक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है । हालांकि भारत को अभी भी चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है—

1—उद्योगों की अनिच्छा:— आपूर्ति श्रृंखला की सीमाओं, निवेश के लिए प्रोत्साहन की कमी, जटिल पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं और पुनः उपयोग । पुनर्चक्रण पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी के समर्थन हेतु सूचना की कमी के कारण उद्योग क्षेत्र चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाने के प्रति अनिच्छुक बना रहा है ।

2—जागरूकता और समझ की कमी:— भारत में बहुत से लोग चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा और इसके लाभों से अवगत नहीं है । जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी पहलों को लागू करने के लिए समर्थन प्राप्त करना कठिन हो जाता है ।

3—अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ :- भारत की और संरचना चक्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन कर सकते के लिए पर्याप्त नहीं है । उदाहरण के लिए देश में पुनर्चक्रण सुविधाओं की कमी है जिससे सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना कठिन हो जाता है ।

4—सांस्कृतिक चुनौतियाँ:— भारत में उत्पादों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के विचार के लिए एक सांस्कृतिक प्रतिरोध भी मौजूद है जिससे उपभोक्ता व्यवहार को बदलना तथा एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ाना कठिन हो जाता है ।

5—डाउन-साइकलिंग:— चक्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि के लिए एक चुनौती है । डाउन साइकलिंग से तात्पर्य मूल सामग्री की तुलना में कम मूल्य और गुणवत्ता वाले उत्पादों में सामग्री को पुनर्चक्रीट करने की प्रक्रिया से है ।

6—अनुसंधान एवं विकास में कमी:— एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए हमारे द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के डिजाइन, उत्पादन, उपभोग और निपटान के तरीके में मौलिक बदलाव की आवश्यकता होती है । इस बदलाव के लिए संसाधन की कमी बर्बादी और पर्यावरण गिरावट की चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार और नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है ।

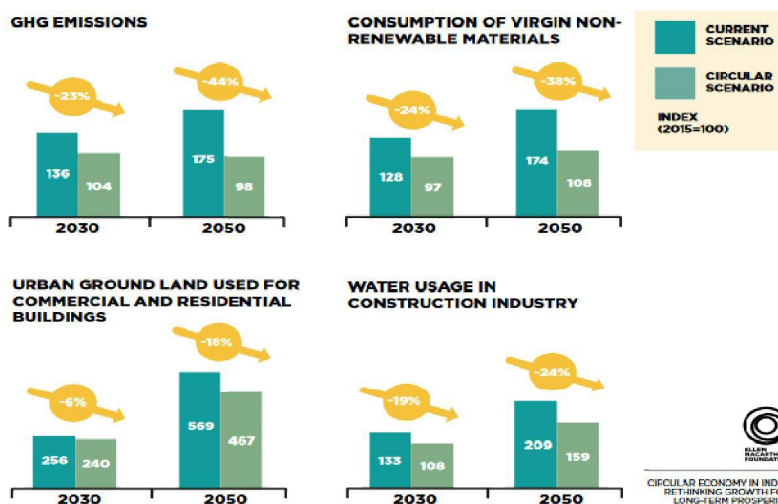


संसाधन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयत्न करती हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण अपना कर व्यवसाय भौतिक लागत बचत प्राप्त कर सकते हैं और मुनाफा बढ़ा सकते हैं। मूल्य सृजन के प्रमुख चालकों में बेहतर उत्पाद डिजाइन नवीन व्यवसाय मॉडल और रिजर्व लॉजिस्टिक्स शामिल है।

(ग)– नकारात्मक बाह्यताओं को कम करना:– एक चक्रीय अर्थव्यवस्था विकास पथ पर नकारात्मक पर्यावरणीय बाह्यताओं को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है।

उदाहरण के लिए वर्तमान विकास परिदृश्य की तुलना में ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2030 में 23% कम और 2050 में 44% कम हो सकता है जिससे भारत को हाल ही में अनुमोदित पेरिस समझौते में वादा किए गए अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह तुलना तीन फोकस क्षेत्रों में संचित उत्सर्जन से ली गई है। अन्य नकारात्मक बाह्यताओं जैसे की नवीन सामग्रियों और पानी के रैखिक उपयोग और सिंथेटिक उर्वरकों की खपत से उत्पन्न होने वाली घटनाओं में भी कमी आएगी।

Comparison of Potential Development Paths



चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में किए गए सरकारी प्रयास:– चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत की नीतिगत रूपरेखा एक बहु आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है। जिसमें नियामक उपाय वित्तीय प्रोत्साहन जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण शामिल है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां और पहल निम्न प्रकार से हैं।

1–राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (एन० आर० ए० पी०):– चक्र का अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति है। एन० आर० ए० पी० को 2019 में टिकाऊ उत्पादन और उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देने संसाधन दक्षता को बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से जारी किया गया था।



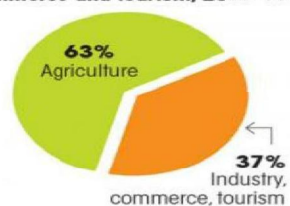
कचरे का अधिकांश हिस्सा लैंडफिल में निपटाया जाता है या खुले स्थानों में फेंक दिया जाता है जिससे पर्यावरण ही गिरावट एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं।

भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। हम पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि अधिक बार और गंभीर सुखा, बाढ़ गर्मी की लहरों और चरम मौसम की घटनाएं अधिक लगातार और गंभीर गर्मी की लहरों के कारण मृत्यु दर और बीमारी में वृद्धि हुई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 15% और रोजगार का 43% है और जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है लगातार गर्मी की लहरें, अत्यधिक वर्षा, पानी की कमी, मिट्टी का क्षरण भारत में कृषि उत्पादन और आय पर सीधा असर डालते हैं बदले में कमी के परिणाम स्वरूप ग्रामीण आय कमजोर होती है और परिणाम स्वरूप मांग कम होती है।

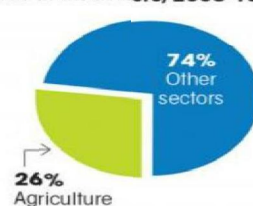
HEIGHTENED THREAT

Given its reliance on weather, agriculture is especially vulnerable to the increased frequency/intensity of extreme weather events

Damage and loss in agriculture relative to combined industry, commerce and tourism, 2008-18



Damage and loss in agriculture as share of total damage and loss in all sectors, 2008-18

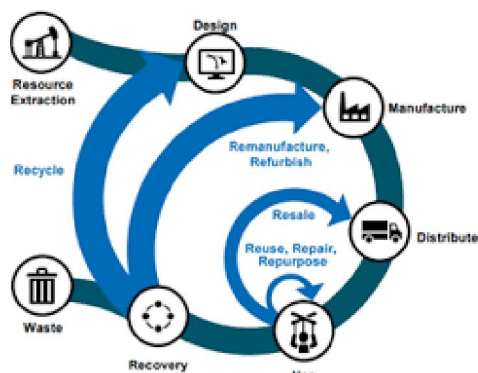


Source: "The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021" by FAO

विकसित भारत के लिए चक्रीय तथा संतत अर्थव्यवस्था की अनिवार्यता:— चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत एक ऐसी प्रणाली में योगदान दे सकते हैं जो भारतीय आबादी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगी। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, भीड़भाड़ और प्रदूषण जैसी नकारात्मक बाह्यताओं को सीमित करने में मदद कर सकता है। इस परिवर्तन के केंद्र में तीन प्रमुख तत्व हैं:— (क)— प्राकृतिक पूंजी का संरक्षण:— खतरे वाले स्टॉक और घटते मीठे पानी के संसाधन, मिट्टी का क्षरण, जैव विविधता की हानि, मछली के स्टॉक की कमी, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण के कारण प्राकृतिक पूंजी को संरक्षित करने और बढ़ाने के महत्व की आवश्यकता होती है। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था का अभ्यास प्रणाली के भीतर पोषक तत्वों के प्रवाह को प्रोत्साहित करके और परिस्थितियों का निर्माण करके प्राकृतिक पूंजी को बढ़ा सकता है। पुर्नजन्म प्रौद्योगिकी और नवकरणीय प्रक्रियाओं का उपयोग सीमित स्टॉक को नियंत्रित कर सकता है और संसाधन प्रवाह को संतुलित कर सकता है। भारत में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था विकास पथ वर्तमान विकास परिदृश्य की तुलना में 2030 में 14 लाख करोड़ रुपये और 2050 में 40 लाख करोड़ का वार्षिक मूल्य बन सकता है। यह निष्कर्ष तीन फोकस क्षेत्रों (कृषि, गतिशीलता और निर्माण) में लागत की तुलना में निकलता है। (ख)— जैविक और तकनीकी घटकों का प्रसार:— उच्च सामग्री खपत पोषक तत्वों की हानि और उत्पादों और सामग्रियों की बर्बादी बढ़ती समस्याएं हैं। यह समस्याएं भारतीय उद्योग के लिए उत्पादों घटकों और सामग्रियों को प्रसारित करने और अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए नवीनीकरण पुनः निर्माण रीसाइकलिंग के लिए समाधान डिजाइन करने का अवसर प्रदान करती है। उत्पादों के जीवन चक्र को बढ़ाने के लिए उनके पुनः उपयोग को अनुकूलित करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। मॉडल साझा करने से उत्पाद उपयोग बढ़ता है। चक्रीय प्रणालियाँ जैविक सामग्रियों के मूल्य को भी अधिकतम करती हैं और कई



आधुनिक व्यावसायिक परिस्थितियों में सीमित संसाधनों, अवशिष्ट संचय, अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण क्षति के कारण संभव हो जाता है। यह ध्यान में रखते हुए के चक्रीय अर्थव्यवस्था उन उत्पादों के अधिकतम उपयोग पर आधारित है जिन्होंने नए संसाधनों के यथासंभव काम दोहन के साथ अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया है। हालांकि हाल के दशकों में चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर जोर बढ़ रहा है।



स्रोत— गूगल इमेज

“चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादों सामग्रियों और संसाधनों का मूल्य यथासंभव लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में बनाए रखा जाता है, और अपशिष्ट उत्पादों को कम से कम किया जाता है।” (मिहाजलोव एट एल: 2019 पृष्ठ 5)

इन परिभाषाओं के आधार पर चक्रीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपशिष्ट या ऐसे उत्पादों का उपयोग करके उत्पादों के उत्पादन पर आधारित है जो बुनियादी कच्चे माल के रूप में अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं और आवश्यक नए संसाधनों की यथासंभव कम निकासी करते हैं तथा सभी की रक्षा के लिए पर्यावरण और संतत विकास हासिल करते हैं।

भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तथा स्थिति:— भारत का वर्तमान आर्थिक मॉडल काफी हद तक रैखिक है। जहां संसाधनों को निकाला जाता है, संसाधित किया जाता है, और उत्पादन में परिवर्तित किया जाता है जो उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं। उपभोग के बाद इन उत्पादों का निपटान कर दिया जाता है जिससे बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है। लगभग आधी सदी के भीतर 1970 से 2015 तक भारत ने अपनी वार्षिक सामग्री खपत में 6 गुना वृद्धि देखी है जो 1.8 अरब टन से बढ़कर सात अरब टन तक हो गया है। जिसके 2030 तक बढ़कर 14.02 बिलियन टन तक पहुंचाने की उम्मीद है। भारत का संसाधन निकर्षण 1680 टन प्रति एकड़ है जो विश्व औसत 450 टन प्रति एकड़ से 251% अधिक है। भारत में पुर्ननवीनीकरण किए गए सामानों का प्रतिशत मामूली 20% है। जबकि अकेले यूरोप में पुर्ननवीनीकरण वस्तुओं की मात्रा 70% तक है। भारत ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भी है और कुल विश्व उत्सर्जन का 9.2% हिस्सा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीओसीबीओ) के अनुसार— भारत हर साल 62 मिलियन टन से अधिक कचरा उत्पन्न करता है। लगभग 45 मिलियन टन (70%) एकत्रित किया जाता है। जिसमें से लगभग 12 मिलियन टन का उपचार किया जाता है तथा 31 मिलियन टन लैंडफिल साइटों पर डंप किया जाता है। इसके 2030 तक बढ़कर 165 मिलियन टन होने की उम्मीद है। इस



काशी नरेश राजकीय पी.जी. कॉलेज ज्ञानपुर, भदोही उत्तर प्रदेश।

प्रस्तावना:— गणतंत्र बनने के 75 साल के भीतर आज भारत विश्व शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। हम जो कर रहे हैं उससे हमारे अपने लोगों के साथ-साथ संपूर्ण विश्व के लिए जबरदस्त संभावनाएं पैदा हुई हैं।

आज भारत संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच के शिखर पर है जो 'निर्माण करो और त्याग दो' की पारंपरिक रणनीति से आगे बढ़ सकता है। देश की युवा आबादी और तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र के मददे नजर ऐसे संरचनात्मक विकल्प हैं जो सरकार द्वारा चुने जा सकते हैं जो इसे लाभकारी पुनर्रयोजी और मूल्य सृजन करने वाले विकास की दिशा में ले जाएंगे। विकास के डिजिटल रूप से सशक्त प्रतिमान के ढांचे के भीतर चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन जिसका उद्देश्य प्रकृति के पुनर्स्थापनात्मक और पुनर्रयोगी है से संसाधनों और ऊर्जा का अधिक कुशल उपयोग हो सकता है।

भारत द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाने से अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है जिसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त वार्षिक लाभ तथा प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। यदि हम अपनी संसाधन दक्षता में सुधार कर सकते हैं, दुर्लभ संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं तथा नए व्यवसाय मॉडल और उधमशीलताउदमों के गठन को प्रोत्साहित कर सकते हैं तो हम आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे।

संतत एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था:— हाल के वर्षों में चक्रीय तथा संतत अर्थव्यवस्था की अवधारणा ने विभिन्न पर्यावरणीय एवं आर्थिक चुनौतियों को संबोधित कर सकते के एक विकल्प के रूप में व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया है। विभिन्न संसाधनों की परिमिति प्रकृति और अपशिष्ट एवं प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों की बढ़ती मान्यता के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पारंपरिक रैखिक मॉडल के लिए एक अधिक संवाहनीय एवं प्रत्यास्थायी विकल्प की पेशकश करती है।

विश्व भर में सरकारें कारोबार क्षेत्र और अन्य संगठन चक्रीय अभ्यासों को अपनाने और अधिकाधिक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के रास्तों की तलाश कर रहे हैं।

उत्पत्ति एवं परिभाषा:— अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेथ बोल्टिंग ने पहली बार 1966 में अपने पेपर “द इकोनॉमिक्स ऑफ द कमिंग स्पेसशिप अर्थ” में चक्रीय अर्थव्यवस्था शब्द का इस्तेमाल किया था। 1990 में अमेरिकी अर्थशास्त्री पीयर्स एवं टर्नर ने “प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का अर्थशास्त्र” नामक पुस्तक में प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के बीच संबंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। हालांकि 21वीं सदी के शुरुआत में चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा के विकास में सबसे बड़ा योगदान एलन मैकाथर फाउंडेशन द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 2010 में आर्थिक क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था के अनुप्रयोग के बारे में निम्न जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई—

1..चक्रीय अर्थव्यवस्था और उसके मूल तत्वों की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं को रेखांकित कर उन बुनियादी सिद्धांतों पर जो देना है जिन पर चक्रीय अर्थव्यवस्था आधारित है।

- चक्रीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी चालकों पर प्रकाश डालना।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने और विकास की बुनियादी रणनीतियों और लक्ष्य को प्रस्तुत करना।

चक्रीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर संतत विकास को प्राप्त करने और बढ़ावा देने का एक साधन है। सतत विकास का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत की अनदेखी न करते हुए वर्तमान मांगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच संतुलन लाना है। यह दुनिया के विभिन्न पहलुओं के विकास की दिशा में काम करने के लिए मनुष्य के उद्देश्य के साथ प्रकृति की आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। अवधारणा का मूल विचार अर्थव्यवस्था के रैखिक मॉडल को प्रतिस्थापित करना है जो



संतत एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था: विकसित भारत के संदर्भ में.

(With Reference to the Circular and Sustainable Economy Developed India)

वीरेन्द्र कुमार

असि०प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)

काशी नरेश राजकीय पी.जी. कॉलेज, ज्ञानपुर, भदोही उत्तर प्रदेश।

Affiliated by MGKVP Varanasi

virendra.rsms@gmail.com

“उस विचार से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जिसका समय आ गया हो”— विक्टर ह्यूगो

शोध सारांशिका (Abstract)

विकसित भारत **Viksit Bharat** का औपचारिक शुभारंभ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने की संभावना मनोरम है। भारत आज कई क्षेत्रों में लगातार विकास की बुलंदियां छू रहा है। आधारभूत संरचना, नवोन्मेष, अंतरिक्ष तकनीक, संसाधनों के संरक्षण जैसे क्षेत्र में हमारे देश का प्रदर्शन बेहद सराहनीय है। शासन संचालन के तौर तरीकों, नीतियों के निर्माण और संस्थाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार से लेकर अंतरराष्ट्रीय मापदंड तैयार करने तक, भारत खुद को आधुनिक राष्ट्र के तौर पर विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में शहरी-ग्रामीण, कृषि- औद्योगिक और संगठित-असंगठित कौशल आदि का अनोखा मिश्रण है। इसी तरह भारत की विकास योजना भी विचारों और प्रणालियों के लिहाज से अलग है।

भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी बसती है और इसके कारण यहां जबरदस्त संभावनाएं हैं। आज भारत संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच के शिखर पर है; और जो “निर्माण करो और त्याग दो” की पारस्परिक रणनीति से आगे बढ़ सकता है। देश की युवा आबादी और तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र के कारण ऐसे संरचनात्मक विकल्प हैं जो सरकार द्वारा चुने जा सकते हैं। जो इसे लाभकारी, पुनर्योजी और मूल्य सृजन करने वाले विकास की दिशा में ले जाएंगे जिससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। “आत्मनिर्भर भारत” बनाने का कदम संतत विकास है। हम तत्काल एक ऐसा विकास प्रतिमान चाहते हैं जो संसाधन दक्षता को अधिकतम करें। बढ़ती जनसंख्या, तेज शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के साथ भारत को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर विकसित होना चाहिए।

भारत द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाने से अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है जिसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त वार्षिक लाभ, भीड़-भाड़ और प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। यदि हम अपनी दक्षता संसाधन में सुधार कर सकते, दुर्लभ संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते और नई व्यवस्था मॉडल और उधमशीलता उद्योगों के गठन को प्रोत्साहित कर सकते तो हम सतत विकास तथा आत्मनिर्भरता की ओर आगे कदम बढ़ाएंगे।

कीवर्ड— चक्रीय अर्थव्यवस्था, संतत अर्थव्यवस्था, पुनर्चक्रण, पुनर्योजित संसाधन दक्षता, परिस्थितिकी संतुलन।

